Rift in the Centre for advanced study in Metallurgy at Banaras Hindu University

1056. SHRI PARVATHANENI UPENDRA:
SHRI VIRENDRA VERMA:
SHRI ISH DUTT YADAV:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether there is a rift between the Banaras Hindu University and the University Grants Commission over the person to head the Centre for Advanced Study in Metallurgy the Banaras Hindu University; and

(b) if so, what action has been taken by Government to resolve the rift to prevent closure of this prestigious institution?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI L. P. SHAHI): (a) and (b) According to the information furnished by the University Grants Commission, Prof. T. R. Anantharaman was Coordinator of the Centre of Advanced Study in Metallurgy at Banaras Hindu University before his superannuation on 30-11-87. Consequent to his superannuation, the matter regarding the Programme Coordinatorship of the Centre of Advanced Study in Metallurgy was discussed by the Executive Council of Banaras Hindu University on 5th December, 1987. The Council resolved to authorise the Vice-Chancellor to make necessary arrangements for Programme Coordinator. The Vice-Chancellor asked the Head of the Department of Metallurgical Engineering to function as Programme Coordinator of the Centre in Place of Prof T. R. Anantharaman.

The University Grants Commission has asked the University to review their decision in the light of its guidelines governing the appointment of Programme Coordinators under the Special Assistance Programme.

रोजगारोन्मुखी शिक्षा का प्रस्ताव

1057. **श्री अजीत जोगी** : क्या **मानव संसाधन** विकास मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विद्यालय स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा के पाठ्यक्रम में ऐसा कोई संशोधन करने का विचार कर रही है जिसमें छात्र हाई स्कूल परीक्षा पास करने से पूर्व कम से कम एक व्यवसाय या तकनीक में निपुणता हासिल कर सकें और वे शिक्षा प्राप्ति के बाद बेकार न रहे ;

(ख) यदि हां, तो शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ग) इस समय विद्यालय स्तर पर व्यावसायिक और तकनीकी संस्थानों में प्रतिवर्ष कितने छात्र दाखिल किये जा रहे हैं और कुल छात्रों में उनका प्रतिशत कितना है ; और

(घ) उक्त संस्थाओं की संख्या में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० साही) : (क) व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में बहुत ही उच्च प्राथमिकता प्रदान की गयी है । इसमें इसके साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि "व्यावसायिक शिक्षा एक ऐसी विशिष्ट शिक्षा होगी जिसका आशय विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुये जाने पहचाने व्यावसायों हेतु छात्रों को तैयार करना है । ये पाठ्यक्रम सामान्यतः माध्यमिक स्तर के पश्चात् पढ़ाये जायेंगे, लेकिन योजना को लचीला रखते हुये, ये शिक्षा VIII के पश्चात् भी उपलब्ध कराये जा सकते हैं ।"

(ख) माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 1987-88 से प्रारंभ की गयी थी जिसके अन्तर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को स्कूलों मे +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने के लिये वित्तीय सहायता दी जा रही है ।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार उच्च माध्यमिक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों मे छात्रों की वर्तमान वार्षिक प्रवेश क्षमता 72000 है जोकि उच्च माध्यमिक स्तर पर प्रवेश पाने वाले छात्रों की कुल संख्या का करीब 2.5 प्रतिशत है ।

(घ) व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत करीब 1000 स्कूलों को शामिल करने के लिये वर्ष 1987-88 में 18 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 32.26 करोड़ रुपये की राशि की वित्तीय सहायता संस्वीकृत की गयी है । योजना के अन्तर्गत शेष राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को शामिल करने के भी प्रयास किये जा रहे हैं । राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निर्धारित किया गया है कि वर्ष 1990 तक 10 प्रतिशत और वर्ष 1995 तक 25 प्रतिशत स्कूलों को शामिल किया जाय ।

Increase in Cancer incidences

1058. SHRI BHAGATRAM MANHAR: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the incidence of cancer in India is increasing, if so, what are the details of various measures being taken by Government to fight the disease;

(g) what is the total expenditure incurred on various anti-cancer programmes every year during the last ten years; and

(c) what is the role and importance of cobalt therapy institutions/hospitals/medical colleges where cobalt therapy units have been installed or are likely to be installed during the Seventh Five Year Plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (KUMARI SAROJ KHAPARDE): (a) The data from Population Based Cancer Registries of the National Cancer Registry Project under the Indian Council of Medical Research does not show any major change in the incidence of cancer from 1982-85. Facilities for treatment of cancer including Radio-Therapy are available in 91 institutions in the country including 9 Regional Cancer Centres. Chereotherapy facilities are generally available in all the major hospitals. There are 74 Medical Colleges with Pap Smearing Units, under the Post Partum Programme with cancer detection facilities. Early Cancer Detection Centres have been set up in 29 institutions.

(b) The expenditure incurred by the Government of India on various anti-cancer programmes during the last 10 years is as given below.—

Year	Expenditure (Rs. in lakhs)	
	Plan	Non-Plan
1978-79	108.17	20 47
1979-80	59.50	22 40
1980-81	151.00	25.40
1981-82	284 87	31.22
1982-83	387.82	32 87
1983-84	308 80	37 31
1984-85	245.67	47.80
1985-86	320.31	64.70
1986-87	420.76	84.41
1987-88	353.90	81.13